ASSOCHAM IN THE NEWS

Amar Ujala

11 June, 2018

नए रोजगार की पैमाइश के लिए प्रणाली की जरूरत

नई दिल्ली। देश को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का खाका तैयार करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली विकसित करने की जरूरत है, ताकि सरकारी नीतियां उसी के मुताबिक बनें। एसोचैम ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही।

उद्योग संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस प्रकार हम हर महीने मुद्रास्फीति के आंकड़े, औद्योगिक उत्पादन से जुड़े आंकड़े तथा जल्दी-जल्दी आने वाले अन्य आर्थिक आंकड़ों को जारी करते हैं, उसी तरह हमें जल्द से जल्द एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करने की जरूरत है, जिससे नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारियों का आंकड़ा भी हर महीने जारी हो। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक हो रहा है, तो रोजगार सृजन का खाका तैयार करने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। एजेंसी

ASSOCHAM IN THE NEWS

Deshbandhu **11 June, 2018**

रोजगार सृजन के आंकड़े जुटाने की भरोसेमंद प्रणाली जरूरी : एसोचैम

नई दिल्ली, 10 जून (एजेंसियां)। उद्योग संगठन एसोचैम ने रोजगार सृजन के आंकड़े जुटाने की भरोसेमंद प्रणाली विकसित करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि इससे सरकारी नीतियां व विभिन्न क्षेत्रों की नीतियां अनुकूल हो पाएंगी। संगठन के महासचिव डी एस रावत ने आज यहां जारी विज्ञप्ति में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब संगठित हो रहा है और ऐसे में रोजगार सृजन के आंकड़ों को इकट्ठा करने में परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए नमूना सर्वेक्षण के पारंपरिक तरीके की जरूरत नहीं। वेतन अब बैंक के माध्यम से दिया जाता है और सिर्फ बैंकों के सैलरी डाटा को जमा करके और इसकी तुलना करके रोजगार सृजन के आंकड़े निकाले जा सकते हैं। एसोचैम के मुताबिक रोजगार सृजन के आंकड़े पता करने का मौजूदा तरीका लचीला है और इससे क्षेत्रवार रोगार सृजन का पता नहीं चल पाता। नए तरीके में सबसे पहले बैंकों में खुले नए सैलरी खाते का आंकड़ा निकालना होगा और पैन नंबर के जरिए यह पता लगाना होगा कि संबंधित व्यक्ति ने सिर्फ नौकरी बदली है या यह नई नौकरी है। संगठन के अनुसार, किसी भी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं ताकि इनके जरिए सरकारी नीतियों को ब्याज दर, कल्याणकारी योजनाओं, निवेश पहल और कराधान के अनुकूल बनाया जा सके। रोजगार आंकड़े जमा करने की शुरुआत पहले संगठित क्षेत्र से कर देनी चाहिए। राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का निर्माण आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए न कि इधर-उधर से प्राप्त जानकारियों के आधार पर। इन आंकड़ों को जमा करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी होनी चाहिए। अधिक विभाग और एजेंसियों को अपने अपने आंकड़े नहीं जारी करने देने चाहिए।

कोट-देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब संगठित हो रहा है और ऐसे में रोजगार सृजन के आंकड़ों को इकट्ठा करने में परेशानी नहीं आएगी।
-डी एस रावत, महासचिव, एसोचैम